राजधानी के अरेरा कॉलोनी स्थित दत्त मंदिर में मराठी समाज द्वारा सावन सोमवार पर जल अभिषेक किया गया वहीं बाणगंगा पीतल मंदिर पर कानबाई पूजा महाराष्ट्रीयन यात्रा निकाली गई।

पचास विद्यार्थियों को मिलेगी निःशुल्क यूपीएससी-एमपीपीएससी कोचिंग

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः जिला प्रशासन की पहल पर आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए इस बार भी यूपीएससी और एमपीपीएससी की निःशुल्क कोचिंग शुरू की जा रही है। इसके लिए सोमवार से पंजीयन प्रक्रिया शुरू हो गई। पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर 50 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। पंजीयन की अंतिम तिथि 31 अगस्त निर्धारित की गई है। निःशुल्क कोचिंग का नया बैच 5 सितंबर से पॉलीटेक्निक चौराहा स्थित हिंदी भवन में शुरू होगा। जिला प्रशासन ने दो वर्ष पहले इस पहल की शुरुआत की थी। इस बार भी ऐसे विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन महंगी कोचिंग फीस वहन करने में सक्षम नहीं हैं। जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में आदर्श परिवार एवं आधुनिक नालंदा द्वारा पं. रविशंकर शुक्ल न्यास के सहयोग से कोचिंग कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। इसमें स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़े लोगों और कॉलेज के प्रोफेसरों की भी मदद ली जाएगी। कोचिंग में विद्यार्थियों को प्रशासनिक अधिकारी भी पढ़ाएंगे। पढ़ाने में रुचि रखने वाले अधिकारी नियमित रूप से एक से दो घंटे की कक्षाएं लेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा- श्रमिकों के कल्याण और सुरक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध

संबल योजना की 11वीं किश्तः 9149 श्रमिकों को मिली 203 करोड़ रुपए की सहायता

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास से मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना 2.0 के हितग्राहियों को सहायता राशि की 11वीं किश्त जारी की। रक्षाबंधन से पहले प्रदेश के 9149 संबल हितग्राहियों के खातों में 203 करोड़ रुपये की अनुग्रह सहायता राशि अंतरित की गई।

डॉ. यादव ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्रमिकों को संबोधित करते हुए कहा कि श्रमिकों की सेवा, कल्याण और खुशी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि श्रमिक अपने परिश्रम से मध्यप्रदेश के विकास में योगदान दे रहे हैं। कठिन समय में श्रमिक परिवारों का साथ देना सरकार का दायित्व है। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिकों के सम्मान और सुरक्षा के लिए राज्य सरकार विशेष कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश में श्रम शक्ति संहिता लागू की गई है और श्रमिकों की सुरक्षा के लिए श्रम स्टार रेटिंग की शुरुआत की गई है। श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से उन्हें सहकारिता से जोड़ने के लिए श्रमणा योजना भी शुरू की गई है।

श्रमिक परिवारों को आर्थिक सहारा

मुख्यमंत्री ने कहा कि संबल योजना 2.0 ने प्रदेश के एक करोड़ 84 लाख से अधिक श्रमिकों को सहारा दिया है। यह योजना विपरीत परिस्थितियों में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर परिवारों को मजबूती प्रदान करती है।

गर्भवती श्रमिक बहनों को मिलेगी 16 हजार रुपये सहायता

मुख्यमंत्री ने बताया कि पात्र गर्भवती श्रमिक बहनों को 16 हजार रुपये की सहायता राशि दी जा रही है। अस्थायी दिव्यांगता पर एक लाख रुपये और स्थायी दिव्यांगता पर दो लाख रुपये की सहायता का प्रावधान है।

संबल सहायता राशि वितरण का विवरण

कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने कहा कि संबल योजना के हितग्राहियों का बैकलॉग खत्म करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इस किश्त में सामान्य मृत्यु अनुग्रह सहायता के 8027, दुर्घटना मृत्यु के 1034, आंशिक स्थायी दिव्यांगता के 66 और स्थायी दिव्यांगता के 22 हितग्राही शामिल हैं। योजना के तहत अंत्येष्टि सहायता के लिए 5 हजार, सामान्य मृत्यु पर 2 लाख, दुर्घटना मृत्यु पर 4 लाख, आंशिक स्थायी दिव्यांगता पर 1 लाख और स्थायी दिव्यांगता पर 2 लाख रुपये की सहायता दी जाती है।

लंबित मांगों को लेकर कर्मचारी संगठनों ने आंदोलन की रणनीति बनाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मध्य प्रदेश अधिकारी, कर्मचारी एवं पेंशनर्स संयुक्त मोर्चे की संयुक्त बैठक अजाक्स भवन स्थित कार्यालय में हुई। बैठक में 25 से अधिक कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। विभिन्न संगठनों के प्रांताध्यक्षों ने कर्मचारियों और पेंशनरों की लंबित समस्याओं पर चर्चा करते हुए सरकार पर मांगों की अनदेखी करने का आरोप लगाया।

बैठक में शिक्षकों की शिक्षक पात्रता परीक्षा, सीपीसीटी परीक्षा, अनुकंपा नियुक्त कर्मचारियों की सेवा से बर्खास्तगी, मंत्रालय के समान समयमान वेतनमान, संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण और आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन का भुगतान विभाग से कराने सहित विभिन्न मांगों पर विचार-विमर्श किया गया। नगर निगम, नगर पालिका, स्वास्थ्य, राजस्व, शिक्षा और पुलिस विभाग के कर्मचारियों के साथ कार्यभारित कर्मचारियों और स्थायी कर्मचारियों से जुड़ी समस्याओं पर भी चर्चा हुई।

25 से अधिक संगठनों की बैठक में चरणबद्ध आंदोलन की तैयारी, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से मांगा जाएगा समय

बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सभी संगठनों की मांगों को शामिल कर संयुक्त मांग पत्र तैयार किया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री, कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष रमेश चंद्र शर्मा और मुख्य सचिव से लंबित मांगों पर चर्चा के लिए समय मांगा जाएगा। बैठक में यह भी तय किया गया कि यदि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव की ओर से प्रतिनिधिमंडल को चर्चा के लिए नहीं बुलाया जाता है तो प्रदेशव्यापी चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा। मोर्चे के पदाधिकारी सभी संभागीय मुख्यालयों में बैठकें करेंगे और पत्रकार वार्ता आयोजित करेंगे। इसके बाद सरकार को हड़ताल का नोटिस देकर चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की जाएगी।

बैठक की अध्यक्षता संयुक्त मोर्चे के अध्यक्ष एमपी द्विवेदी ने की। आभार प्रदर्शन मुकेश मौर्य ने किया।

निर्जल अनशन पर बैठे अभ्यर्थी की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल जाने से किया इन्कार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मध्यप्रदेश में वर्ग-2 माध्यमिक और वर्ग-3 प्राथमिक शिक्षक भर्ती-2025 में पदवृद्धि की मांग को लेकर नीलम पार्क में चल रहा अनिश्चितकालीन धरना सोमवार को गंभीर स्थिति में पहुंच गया। आंदोलनकारी अभ्यर्थियों के अनुसार ब्यावरा निवासी नरेंद्र राजपूत पिछले चार दिनों से निर्जल अनशन पर हैं। रविवार को दरम्यानी रात करीब तीन बजे उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें चक्कर और कमजोरी की शिकायत हो रही है।

धरना स्थल पर मौजूद अभ्यर्थियों ने प्रशासन को इसकी सूचना दी। आंदोलनकारियों के अनुसार पुलिस प्रशासन पहले भी नरेंद्र को अस्पताल ले जाने का प्रयास कर चुका है, लेकिन उन्होंने अस्पताल जाने से इनकार कर दिया। नरेंद्र का कहना है कि जब तक सरकार पदवृद्धि को लेकर ठोस आदेश जारी नहीं करती, तब तक वह धरना स्थल से नहीं हटेंगे। उन्होंने धरना स्थल पर ही चिकित्सकों की टीम से स्वास्थ्य जांच कराने की मांग की है।

अभ्यर्थियों की मांग है कि वर्ग-2 में प्रत्येक विषय के तीन हजार पद बढ़ाए जाएं और वर्ग-3 में कुल 25 हजार पद किए जाएं। इसके साथ बढ़े हुए पदों पर दूसरी काउंसलिंग कराने की मांग की जा रही है। अभ्यर्थियों का दावा है कि शिक्षा विभाग में बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं, लेकिन भर्ती में पर्याप्त पद शामिल नहीं किए गए।

नीलम पार्क में कई महिला अभ्यर्थी भी अपने बच्चों के साथ धरने पर बैठी हैं। उनका कहना है कि पार्क में मच्छरों, पानी और शौचालय की समस्या के बावजूद वे मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखेंगी। अभ्यर्थी 21 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं।

रफ्तार पर रोक....

तेज बारिश से यातायात प्रभावित, जाम

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राजधानी में सोमवार को हुई तेज बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई और कई प्रमुख मार्गों पर जाम की स्थिति बन गई। दफ्तर से लौटने वाले लोगों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

बारिश के दौरान सड़कों पर पानी भरने से कई स्थानों पर वाहन धीरे चलते नजर आए। व्यस्त मार्गों पर कारों, बसों, ऑटो और दोपहिया वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। निचले इलाकों में जलभराव के कारण आवागमन प्रभावित हुआ। शहर के प्रमुख बाजार क्षेत्रों और मुख्य सड़कों पर यातायात का दबाव बढ़ गया। बारिश के बीच लोग छाते और रेनकोट के सहारे अपने गंतव्य तक पहुंचने की कोशिश करते रहे। वाहन चालकों को जाम के कारण अतिरिक्त समय लगाना पड़ा।

बारिश के बीच लोगों को हुई परेशानी

जेटली की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित

नप्र, भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पद्म विभूषण श्रद्धेय अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉ. यादव ने अपने संदेश में कहा कि श्रद्धेय जेटली के प्रखर विचार, ओजस्वी वाणी एवं राष्ट्र सेवा के प्रति उनका समर्पण, भावी पीढ़ियों को सदैव देश भक्ति की प्रेरणा देता रहेगा।

मुख्यमंत्री ने राजगुरु की जयंती पर किया नमन

नप्र, भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने माँ भारती के वीर अमर सपूत, क्रांतिकारी शहीद शिवराम हरि राजगुरु की जयंती पर सादर नमन किया। डॉ. यादव ने अपने संदेश में कहा कि श्रद्धेय राजगुरू ने जेपी सौंडर्स को मौत के घाट उतारकर और सेंट्रल एसेंबली में बम धमाकों से दमनकारी ताकतों की जड़ें हिला दीं।

त्यौहार से पहले खाद्य विभाग की कार्रवाई

150 किलो मावा, 166 किलो मिल्क केक जब्त

आईएसबीटी और नादरा बस स्टैंड पर जांच में गुणवत्ता पर संदेह, नमूने प्रयोगशाला भेजे

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः रक्षाबंधन और आगामी त्योहारों को देखते हुए खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने सोमवार को भोपाल के बस स्टैंडों पर जांच अभियान चलाया।

आईएसबीटी और नादरा बस स्टैंड पर बाहर से बसों के जरिए भोपाल लाए जा रहे मावा और मिल्क केक की जांच की गई। मिलावट या गुणवत्ता को लेकर संदेह होने पर 150 किलो मावा और 166 किलो मिल्क केक जब्त किया गया। नादरा बस स्टैंड पर नागपुर के रास्ते भोपाल लाई जा रही खाद्य सामग्री की जांच की गई। जब्त 150 किलो मावा की कीमत करीब 45 हजार रुपये आंकी गई है। इसकी बुकिंग अरीहंत डेयरी, भोपाल के नाम पर की गई थी। वहीं 166 किलो मिल्क केक की कीमत करीब 33 हजार रुपये बताई गई है। इसकी बुकिंग सब्जी मंडी स्थित लवली स्वीट्स के नाम पर की गई थी।

खाद्य विभाग की टीम ने जब्त मावा और मिल्क केक के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार, जांच रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और संबंधित नियमों एवं विनियमों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।

त्योहारों के मद्देनजर खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीमें बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर लगातार जांच कर रही हैं। हलालपुरा, आईएसबीटी और नादरा बस स्टैंड के अलावा भोपाल, बैरागढ़, निशातपुरा और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर भी निगरानी की जा रही है। मावा, मिल्क केक, मिठाई, घी, पनीर और अन्य दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता की जांच जारी रहेगी।

सेवा बहाली की मांग को लेकर पेसा मोबिलाइजरों का धरना

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य करने वाले पेसा मोबिलाइजरों ने सेवा बहाली की मांग को लेकर सोमवार से अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया। पंचायत पेसा मोबिलाइजर कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारी डॉ. भीमराव अंबेडकर पार्क में धरने पर बैठे हैं। संघ का कहना है कि प्रदेशभर के हजारों पेसा मोबिलाइजरों को अचानक सेवा से अलग कर दिया गया, जिससे उनके सामने रोजगार और परिवार के भरण-पोषण का संकट खड़ा हो गया है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कुमार कुड़ापे ने बताया कि कर्मचारी लंबे समय से सेवा बहाली, स्थायी नीति बनाने और लंबित मानदेय जारी करने की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में शासन-प्रशासन को कई बार ज्ञापन दिए गए, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। मोबिलाइजरों का कहना है कि उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों में पेसा कानून के प्रावधानों को लागू कराने, ग्रामसभाओं को मजबूत करने और सरकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाने का काम किया है।

नारियलखेड़ा में मकान टूटने से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की मांग

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः नारियलखेड़ा क्षेत्र में हाल ही में हुई प्रशासनिक कार्रवाई में मकान टूटने से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और राहत की मांग को लेकर ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल मध्य प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल से मुलाकात की।

काउंसिल ने आवेदन देकर प्रभावित परिवारों का सर्वे कराने, तत्काल राहत देने और वक्फ की खाली जमीनों की पहचान कर पात्र परिवारों के लिए वैकल्पिक आवास की व्यवस्था पर विचार करने की मांग की। काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी उमर असलम ने बताया कि कार्रवाई के बाद कई परिवारों के स्कूल बैग, कपड़े, फर्नीचर, जरूरी दस्तावेज और कैंसर मरीजों की दवाएं तक मलबे में दब गईं। बारिश के मौसम में मकान टूटने से परिवारों के सामने रहने का संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने प्रभावित परिवारों के लिए स्थायी समाधान की जरूरत बताई।

काउंसिल ने नारियलखेड़ा और आसपास की वक्फ की खाली जमीनों तथा खसरों की स्थिति की जांच कराने की मांग की। कांग्रेस नेता मोहम्मद जहीर और नायब शहर काजी मौलाना अली कदर ने भी प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए कानूनी रास्ता तलाशने की बात कही। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष सनवर पटेल ने कहा कि करीब 24 मकान न्यायालय के आदेश के बाद हटाए गए हैं। उन्होंने अधिकारियों को मामले की कानूनी स्थिति देखने के निर्देश दिए। पटेल ने कहा कि वक्फ बोर्ड कानून से बंधा है और वक्फ संपत्ति का उपयोग वाकिफ की मंशा के अनुसार ही किया जा सकता है। यदि संपत्ति की आय जरूरतमंदों की मदद के लिए निर्धारित है तो कानून के तहत सहायता का प्रयास किया जा सकता है।

संवाद

रवीन्द्र भवन में मध्यप्रदेश युवा आयोग द्वारा आयोजित कृषि नवाचार संवाद कार्यक्रम

कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान : मुख्यमंत्री

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश को दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है। किसानों की आय बढ़ाने, युवाओं को आधुनिक खेती से जोड़ने और कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

रवीन्द्र भवन में मध्यप्रदेश युवा आयोग द्वारा आयोजित कृषि नवाचार संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कृषि विद्यार्थियों, किसानों, कृषि उद्यमियों और नवाचार करने वाले युवाओं से संवाद किया। उन्होंने कहा कि खेती अब पारंपरिक तरीकों तक सीमित नहीं है। युवा नई तकनीक अपनाकर खेती के साथ पशुपालन, मत्स्य पालन, बकरी पालन और मुर्गी पालन को भी आय का माध्यम बनाएं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ समझौता किया गया है। किसानों को दूध के दाम पहले की तुलना में 8 से 10 रुपये प्रति लीटर अधिक मिलने लगे हैं। प्रदेश में प्रतिवर्ष एक लाख गिर नस्ल की बछिया तैयार करने की योजना भी जल्द लागू की जाएगी। पशुपालकों को उन्नत नस्ल उपलब्ध कराने के लिए डॉ. भीमराव आंबेडकर कामधेनु योजना शुरू की गई है।

उन्होंने कहा कि सरकार अगले पांच वर्षों में सिंचाई का रकबा बढ़ाकर 100 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। जिला और संभाग स्तर पर कृषि नवाचार संवाद आयोजित किए जाएंगे। प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के साथ बहुफसलीय खेती, खाद्य प्रसंस्करण और कृषि आधारित उद्यमिता पर भी जोर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती को लाभ का व्यवसाय बनाना सरकार का प्रमुख लक्ष्य है।